

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :- 125/2021**

**रजिस्ट्रेशन सं० :- 2021/123**

**बउनवान**

- 1- पंसुरीबाई आयु 70 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी अर्जुन जाति मेहर निवासी छैलाबेल हाल फतेहपुर तहसील बारों जिला बारों (राज.)
- 2- शांतिबाई आयु 57 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी नेताराम जाति मेहर निवासी मण्डोला तहसील बारों जिला बारों (राज.)

**(अपीलांटगण)**

**बनाम**

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति मेहर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारों (राज.)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू जिला बारों

**(रेस्पोंडेन्टगण)**

**अपील विरुद्ध तहसीलदार अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित आदेश दि. 16.06.2020 की पालना मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 की अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि०, 1956**

- उपस्थित :-
- 1- श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
  - 2- श्री बृजराज किशोर शर्मा (रेस्पों. क्रम 1)
  - 3- परोकार सरकार (रेस्पों. क्रम 2)

**निर्णय दिनांक 04.04.2022**

अपीलांटगण द्वारा जयें विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 की पालना मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 दिनांक 23.06.2020 ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू की अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध रेस्पोंडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 26.03.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जयें सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 द्वारा जयें अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोंडेन्ट क्रम 2 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम छैलाबेल की आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.38 हेक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 0.98 हेक्टर का एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर इंतकाल खोला गया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में विधि का सही तरीके से विवेचन नही किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती और यदि पैतृक सम्पत्ति मे अपने हिस्से की वसीयत की जाती है तो समस्त वारिसान को सुना जाना आवश्यक है। जबकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 20 दिन मे बिना मृतक खातेदार के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय व नामान्तकरण खोला गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि प्रस्तुत वसीयत दिनांक 08.05.2000 की है तथा खातेदार की मृत्यु दि. 01.01.2001 को हुई है तो उक्त आराजी की खातेदारी तथा वसीयत जांच के लिये आवेदन 19 साल देरी से पेश करने का कारण न्यायालय ने कही भी स्पष्ट नहीं किया है जिससे राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों एवं रेस्पोंडेन्ट क 1 की मिली भगत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण आवेदन दि. 27.05.2020 तथा निर्णय दिनांक 16.06.2020 को मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तथा फर्जी व कूटरचित वसीयत के गवाह बयान लेकर एक तरफा रूप से कर दिया जो विधि विरुद्ध है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि अनरजिस्टर्ड वसीयत की जांच तहसीलदार द्वारा की जाती है तब मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों की रिपोर्ट ली जाकर तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना होता है परन्तु हस्तगत अपील में ऐसा नहीं कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांतगण मृतक कन्हैयालाल की सगी भतीजियाँ हैं तथा कन्हैयालाल द्वारा ही अपीलांतगण की शादी-ब्याह व कन्यादान किया गया था। इस कारण अपीलांतगण मृतक खातेदार के विधिक वारिसान हैं तथा उक्त निर्णय से उनके हित प्रभावित हुये हैं। चूंकि अपीलांतगण अपील में पक्षकार नहीं थे, इस कारण धारा 96 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2020 की पालना में खुले इंतकाल नम्बर 445 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करे कि मृतक खातेदार के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर तथा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

**रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.06.2020 की पालना में खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 दि. 23.06.2020 ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त वसीयत में गवाह चौथमल, जगदीश, पूरणमल, जमनाबाई, बद्रीलाल आदि के बयान लिये गये हैं एवं पटवार मण्डल खुरी की रिपोर्ट ली गई है। प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रेवेन्यु) अधिनियम, 1956 की धारा 135 (2) और 175 के अन्तर्गत आता है जिसमें नामान्तकरण का प्रकरण अविवादित नहीं होकर विवादित था। नामान्तकरण स्वीकृति का आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत आता है और ऐसे आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है और निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा सम्भागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

**प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक** की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अपीलांत के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि हमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया और रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि वसीयत में गवाह आदि के बयान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिये गये हैं। इसके पश्चात इंतकाल खोला गया है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधि०

की धारा 135 (2) और 175 के अन्तर्गत आता है जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को है। इस पर प्रकरण मे राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रेवेन्यु) अधिनियम, 1956 धारा 135 (2) और 175 का अवलोकन किया गया जिसके तहत उक्त प्रकरण विवादित होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है और निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा सम्भागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अपीलांतगण सक्षम न्यायालय मे उक्त आदेश/इंतकाल की अपील प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **04.04.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)  
अति० जिला कलक्टर  
बारों